...(Interruptions)... Mr. Ahluwalia, you are a senior Member. *...(Interruptions)...* You are a senior Member. You are not right; you are wrong. *...(Interruptions)...* You are wrong. *...(Interruptions)...* You need not decide what is fair. I don't need your certificate of fairness. *...(Interruptions)...* I do not need your certificate. *...(Interruptions)...* You please go back to your seats. *...(Interruptions)...* You please go back to your seats. *...(Interruptions)...* This is a Zero Hour Mention. आपको यह मालूम था। मि. पाणि, यह क्या हो रहा है? *...(Interruptions)...*The House is adjourned till 2 o'clock.

The House then adjourned at forty-four minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled, after lunch, at two of the clock,

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

THE APPROPRIATION (NO.3) BILL, 2008

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2008-2009, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I present the first batch of Supplementary Demands for Grants, 2008-2009. The first batch of Supplementary Demands for Grants includes 97 grants and 4 appropriations. Authorisation is being sought for gross additional expenditure of Rs. 2,37,285.84 crores, of which the cash outgo will be Rs. 1,05,613.38 crores and the others are technical supplementaries and the token provision is 0.17 crores. Of the cash outgo of Rs. 1,05,613.38 crores, an amount of Rs. 1,04,243.98 crores – that is, 99 per cent of the cash outgo – is on 13 major items. They are, (1) fertilizer subsidy, (2) Sixth Central Pay Commission arrears, (3) farmers' debt relief and debt waiver, (4) National Rural Employment Guarantee Scheme, (5) additional Central assistance to the States, (6) food grains subsidy, (7) payment to the IMF consequent on India's quota being increased, (8) increase in the subsidy for import of edible oil, (9) contribution for the social window of SAARC, (10) pass through assistance to the Delhi Metro Rail Corporation, (11) settlement of pending claims of interest subvention in respect of rupee export credit, (12) construction of permanent shelters for tsunami affected people, (13) technology upgradation fund scheme. Sir, of the net cash outgo of Rs. 5,616.97 is on capital account.

I sincerely hope that the House will accept that these additional demands are absolutely necessary; they are necessary to continue and sustain the programmes that I have listed. I hope, after discussion, the House will be able to vote the Supplementary Demands for Grants and return the Appropriation Bill.

The question was proposed.

श्री यशवंत सिन्हा (झारखण्ड): धन्यवाद, उपसभापति जी। महोदय, जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स कल इस सदन में पेश हुई थीं और जिनके बारे में अभी वित्त मंत्री जी ने कुछ और डिटेल्स बतायीं, उन्हीं पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपसभापति जी, मैं इस बात से अवगत हूं कि इस सदन की एक सीमा है। हम इन पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन हमें इन्हें दूसरे सदन को सिर्फ रिटर्न करना होता है और अगर हम रिटर्न ना भी करें, तो भी संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत इनको 14 दिनों के बाद पारित माना जाएगा। लेकिन यह जो चर्चा करने का अवसर हमें मिला

है, मैं मानता हूं कि यह अत्यंत उपयोगी है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स में हैं और पूरी अर्थ-व्यवस्था के हालात इतने गंभीर हैं कि उन पर अगर यह सदन कुछ विचार करे, तो मुझे लगता है कि उससे काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स वित्त मंत्री जी ने यहां पेश की है, आप उन पर नजर दौड़ाएं, आप इसकी मोटाई देखिए - यह सप्लीमेंटरी डिमांड्स की प्रति है और यह है बजट की प्रति। सप्लीमेंटरी डिमांड्स की कॉपी मोटी है और बजट की कॉपी पतली है। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर मेरे आंकड़ों में कहीं कोई त्रुटि है, तो उसको सुधार लें। मैंने अपनी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से पता करने की कोशिश की है कि वित्त मंत्री जी ने जो पिछले चार बजट पेश किए थे, उनमें उन्होंने किस प्रकार की सप्लीमेंटरी डिमांड्स रखी थीं, जिनको हम साल में बढ़ाते चले गए। मैं सदन के साथ इस आंकड़े को शेयर करना चाहूंगा, चूंकि यह पहला सप्लीमेंट्री है, हालांकि इस बार कुछ समय ज्यादा गुजर चुका है। पहला सप्लीमेंट्री, जो इन्होंने 2004-2005 के बाद पेश किया, उसमें उस साल केवल दो ही सप्लीमेंट्री हुए थे, पहले सप्लीमेंट्री में Net cash outgo Rs. 5,063 करोड़ था। दूसरे सप्लीमेंट्री में Net cash outgo 8,072 crore था। Eight plus five, it is roughly 13,000 crore rupees, 2005-06 में, First Supplementary net cash outgo was 6,818 crore of rupees, Second Supplementary the net outgo was only 1,965 crore rupees and in the Third Supplementary the net outgo was 8,565 crore rupees. About 16, 17 हजार करोड़ का पूरे साल में Net cast outgo हुआ था through the Supplementary Demands. 2006-07 में, उसी प्रकार फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सेकंड सप्लीमेंट्री, थर्ड सप्लीमेंट्री को अगर हम देखें तो मोटी-मोटी वही सिचुयेशन थी। 2007-08 में भी लगभग वही हाल था, दस हजार, बारह हजार, 16 हजार करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड्स होती रही हैं।

उपसभापति महोदय, मैं इस सदन में इस बात को कुछ जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह पहला मौका है पिछले पांच वर्षों में जब कि Net cash outgo इस सप्लीमेंट्री में, it is 1,0,500 crores of rupees and the total, including Technical Supplementaries, is Rs. 2,37,000 crores. In this document the Finance Minister had told us when he presented the Budget. कि उनका टोटल एक्सपेंडिचर इस साल होगा 7,50,000 crores. इसमें अब जो सप्लीमेंट्री मांगा जा रहा है, अगर हम Net cash outgo का लें that is 105000 crore rupees. उपसभापति महोदय, मैं यहां पर इस बात को क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि इस सदन में इस चेहरे को हर कोई पहचानता है, "हंसता हुआ नूरानी चेहरा"। यह वित्त मंत्री जी की पुस्तक है और उन्होंने जो बहुत सारे कॉलम्स लिखे थे, उनको इकट्ठा करके, यह पुस्तक छापी गई है। इसकी मीडिया में बड़ी चर्चा हुई। जब इस पुस्तक का विमोचन हो रहा था तो उस समारोह में बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने भाग लिया। हमारे वर्तमान वित्त मंत्री जी की बहुत प्रशंसा की गई कि इन्होंने इतनी बढ़िया पुस्तक लिखी है। इस किताब में बजट पर एक चैप्टर है। इसमें वर्तमान वित्त मंत्री जी ने हर चैप्टर से पहले एक पैराग्राफ लिखा है। उन्होंने जो कहा है, मैं उसको कोट करता हूं,

"Any Budget is a mixed bag. A Budget is judged wrongly, in my view, on the day, it is presented, it should be marked only after the financial year is over. Once upon a time, Budgets had an inviolable sanctity. Later, Budgets became a bag of tricks and Budget figures lost all meaning. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act has brought some discipline. Nevertheless, we still make..." and I am quoting this with emphasis "...unfunded Budget provisions. We still borrow too much and many ministries cannot spend the money given to them, yet, ask for more." This is what the Finance Minister said as Finance Minister in this Book. Budget has an inviolable sanctity. Sir, where is that sanctity of the Budget? मैं यह पूछना चाहता हूं। मेरा उससे ऐतराज नहीं था, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। आपने 60,000 करोड़, जो बढ़कर 65,000 करोड़ 70,000 करोड़ हुआ, आपने कहा कि हम फार्मर्स, लोन वेवर्स के लिए सैंक्शन करेंगे। आपने बजट में एक लाइन बोल दी, लेकिन क्या बजट में उसका प्रोविजन रखा गया? नहीं। उसका प्रोविजन निल था। एक्सपेंडिचर बजट देखिए। रेलवे मिनिस्टर ने सिक्स्थ पे कमीशन के लिए अपने बजट में प्रावधान किया, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में सिक्स्थ पे कमीशन के लिए कोई

प्रावधान नहीं किया। फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, फूड सब्सिडी हो, वित्त मंत्री जी ने उसे अंडर फंडड रखा। ऑयल बॉण्ड्स और ऑयल अंडर रिकवरीज की बात मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा। ठीक है, वित्त मंत्री जी आए हैं, हम इन्हें पैसा देंगे, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मैं इस सदन में गंभीरता से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम इसी तरह बजट बनाना चाहते हैं? वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते समय बहुत गर्व के साथ कहा कि फिस्कल डेफिसिट को हमने 2.5% ऑफ दि जी.डी.पी. पर रोक दिया और उन्होंने इस बात का क्रेडिट लिया कि फिस्कल रिस्पॉंसिबिलीटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत इनको फिस्कल डेफिसिट को 3% पर रखना था, लेकिन वित्त मंत्री जी काबिल हैं, इसलिए काबिल वित्त मंत्री जी ने क्या किया, उन्होंने उसे 2.5 पर ला दिया और जब इनसे कोई सवाल पूछे कि फार्मर्स लोन वेवर्स का क्या होगा, जब कोई इनसे सवाल पूछे कि सिक्स्थ पे कमीशन का क्या होगा, जब कोई इनसे सवाल पूछे फर्टिलाइजर्स सब्सिडी, फूड सब्सिडी का क्या होगा, नरेगा का जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है, उसका क्या होगा, वे कहते थे मेरे पास 0.5% का फिफ्टी बेसिस प्वाइंट्स है, मैं 3% तक जा सकता हूं, मैंने 2.5% पर रखा है। मेरे पास आधे परसेंट का कुशन है। इसी सदन में इनके पहले बजट पर बोलते हुए मैंने यहीं पर टिप्पणी की थी कि वित्त मंत्री जी ने जब अपना पहला बजट पेश किया था तो उसमें उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसे एलोकेट नहीं किया, किसी मंत्रालय को नहीं दिया। 10,000 करोड़ रखा और 10,000 करोड़ रखने के बाद जब कोई उनसे पूछे कि यह कैसे होगा, उन्होंने कहा कि मैं हूं ना। वह जो 10,000 करोड़ रुपया है, उसमें से दूंगा। यह 50,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा, वह 10,000 करोड़ रुपया है ना। 0.5 per cent of the GDP मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं will be about Rs. 25,000 Crores. पच्चीस हजार करोड़ रुपए में पूरी भारत सरकार समा गई और जब कोई वित्त मंत्री से बजट की बात पूछे कि यह कहां से आएगा, वह कहां से आएगा, इनका जवाब था 0.5% का कुशन है ना। उपसभापति महोदय मैं, पूछना चाहता हूं कि फिस्कल रिस्पॉंसिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट एक्ट का क्या हुआ? उन्होंने पहले बजट में ही 2004-2005 में उसके टारगेट्स को एक साल से आगे बढ़ा दिया। उसके बाद इनकी जिम्मेदारी थी कि रेवेन्यू डेफिसिट को इस बजट में निल करके दिखाते। रेवेन्यू डेफिसिट इस बजट में 1% है और हम सब जानते हैं, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि capital expenditure is only Rs. 5,000 crores. That means, Rs. 100,000 crore is revenue expenditure. We know that all these expenditures are on Revenue Account.

उपसभापति महोदय, मैंने यह तय किया था कि मैं सिर्फ इसी सरकार के डॉक्युमेंट्स कोट करूंगा, अपनी बात नहीं कहूंगा। पता नहीं रंगराजन साहब यहां पर बैठे हैं या नहीं, वैसे वह इस सदन के सदस्य हो गए हैं, रंगराजन साहब Prime Minister's Economic Advisory Council के अध्यक्ष थे। अभी इस साल जुलाई में उन्होंने यह रिपोर्ट दी और यह रिपोर्ट है, Economic Outlook for 2008-2009. मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। जो उन्होंने कहा है, उसे मैं कोट कर रहा हूं, "Despite appreciable fiscal consolidation, large and growing off Budget liabilities are, however, a matter of concern. When these are included, the fiscal situation no longer looks stable and sustainable. In 2007-08, the Revised Estimate of fertilizer subsidy is Rs. 30,501 crores and an additional Rs. 7,500 crores is provided by way of bonds to the fertilizer companies. For 2008-09, the subsidy is Budgeted at Rs. 30,985 crores. Given the increase in the feedstock prices and the price of imported fertilizer, the total fertilizers for 2008-09 is likely to be more than Rs. 95,000 crores. Thus, underestimation on this account alone amounts to 1.2 per cent of the GDP. In addition, food subsidy is under-provided in the Budget and together with the fertilizer subsidy the underestimation could easily be more than 2% of the GDP."

उसके बाद उन्होंने बाकी जो ऑयल बॉंड्स वगैरह की बात कही है, उसमें उन्होंने कहा है, "Total off Budget liabilities of the Centre could exceed 5 per cent of the GDP over and above the Budgeted Central deficit figure of 2.5 per cent of the GDP. कहां है हम? और इस बजट का क्या मतलब है? मैं तो कहता हूं कि इस बजट के डॉक्यूमेंट्स को मूंगफली वाले को बेच देना चाहिए ताकि वह इससे मूंगफली का दोना बना कर लोगों को दे।

उपसभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही है इस बजट की sanctity? क्या यही sanctity बची है इसमें? Sir, 5 per cent of the GDP is Rs. 2,50,000 crores. Sir, 5 per cent of the GDP will push the total fiscal deficit of the Central Government to, at least, 7.5 per cent. It will push up the revenue deficit of the Central Government to 6 per cent of the GDP. और हम बजट में कह रहे हैं 2.5%, हम बजट में कह रहे हैं 1%, हम किसको धोखा दे रहे हैं? बजट में यह तिकड़म क्यों हो रही है?

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह जो किताब लिखी है, इसमें इन्होंने जो बातें लिखी हैं, क्या वह भूल गए उन्हें? मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। इन्होंने जसवन्त सिंह जी के बजट पर काफी टिप्पणी की थी। उस समय तक मैंने वित्त मंत्रालय छोड़ दिया था, इसलिए मैं इनके क्रिटिसिज्म से काफी कुछ बचा रहा, लेकिन जसवन्त सिंह जी को इन्होंने हर मुद्दे पर आढ़े हाथों लिया। यह कह रहे हैं, "It is a pity that Mr. Singh does not realise that the Central Government expenditure is a bottomless pit and more he gives to the Ministries, Departments the more they will spend. The only course open to him was to downsize the Government, abolish departments, scrap useless programme and voluntarily retire a substantial number of Government servants..." There was not a whisper about it in the 135-minute Budget Speech of Mr. Jaswant Singh. यह lament है वित्त मंत्री महोदय का। उन्होंने क्यों नहीं departments abolish किए, उन्होंने क्यों नहीं मिनिस्ट्रीज़ एबोलिश किए, उन्होंने सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की क्यों नहीं छुट्टी कर दी? यह कॉलम इन्होंने 2nd March, 2003 को लिखा था। 5 साल बाद मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यह भूल गए? यह जो सीख, जो नसीहत श्री जसवन्त सिंह जी को दे रहे थे, इन पांच सालों की बजट मेकिंग में वित्त मंत्री जी अपनी ही दी हुई नसीहत भूल गए? एक बार भी कौन-सा डिपार्टमेंट इन्होंने abolish किया, कितने कर्मचारियों की छँटनी की, क्या किया इन्होंने, कहां सब्सिडी कम किया? कुछ नहीं किया। उसके बाद जो सबसे तकलीफ की बात है, उपसभापति महोदय, सबसे तकलीफ की बात यह है कि बजट में इतनी बड़ा * होगा? इसमें इस तरह किया जाएगा, * in the Budget? मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि आज के दिन we are back to the bad old days. यह जो 5th Pay Commission की जिम्मेदारियां छोड़ कर गए थे, उसके चलते जो fiscal deficit बढ़ा था और जो यह सदन में लौट कर आए तो उसके लिए हमको आड़े हाथों ले रहे थे। आज फिर वही करके यह सरकार छोड़ेगी। दूसरे के ऊपर डाल दो। Scorched earth policy after me the deluge मुझे कोई चिन्ता नहीं है। मैं क्यों यह सब बातें कह रहा हूं, क्योंकि न बजट में कोई sanctity रही, न ये supplementary demands में कोई sanctity रही, किसी चीज़ की कोई sanctity नहीं है और इसलिए अगर विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा है तो हम कैसे विश्वास कर लें कि 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपए का जो net cash out go है, वही रहेगा, वह आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर वह 95 thousand crores जो Economic Advisory Council of the Prime Minister कह रही है कि सिर्फ fertilizer subsidy है, मेरा मानना है कि वह शायद 1 लाख 30 हजार करोड़ के आसपास है और यह प्रावधान कर रहे हैं additional 60,000 Crores का। आज भी supplementary demands में under provisioning हो रहा है। क्या किया जाए? बहुत चिन्ता का विषय है।

मैं इस बात को उठाने के बाद इस बात पर आता हूं कि ठीक है, इनको तो हम लोग पैसा देंगे, रोक नहीं सकते। यह पैसे ले जाएँ, फिजूलखर्ची करें, जो मरजी में आए वह करें, लेकिन जो गम्भीर बिंदु मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से, उपसभापति महोदय, रखना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे देश में आज का जो वर्तमान आर्थिक संकट है उसके लिए अमेरिका का संकट उतना जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए इस देश में हमारे द्वारा पैदा किया हुआ संकट सही मायने में यह संकट लाया है। बदइंतजामी, हमारी economy का mismanagement, अगर यह इतना बड़ा fiscal deficit run करेंगे, तो इसी पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि अगर fiscal deficit इतना होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा investment के ऊपर, उसका प्रभाव पड़ेगा current account deficit उसका इतना व्यापक प्रभाव पड़ेगा हमारी अर्थ व्यवस्था के ऊपर कि हम उसकी शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब हम सरकार

* expunged as ordered by Chair.

में थे और यह हमारे ऊपर बोझ छोड़ कर गए थे तो हम लोगों ने Fiscal Responsibility And Budget Management Act बनाया था कि हम उसमें धीरे-धीरे कर के fiscal deficit को कम करें।

उपसभापति महोदय, जब मैं वित्त मंत्री था तो एक दफा दूसरे सदन में जब मैं बार-बार fiscal deficit की बात करता था तो कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने मुझे fiscal terrorist की भी संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि "Yashwant Sinha is a fiscal terrorist." मैं उस चार्ज को स्वीकार करता हूं, because if you are not a fiscal terrorist you cannot manage the economy of this country. अब आप देखिए, आज की जो स्थिति है, उसमें क्या है? इन्हीं का Economic Survey, जो इन्होंने इस साल बजट के पहले प्रिजेंट किया...। उस में क्या कहा गया है? "The decisive change in growth trends also means that the economy was, perhaps, not fully prepared for the different set of challenges that accompany fast growth." महोदय, फास्टर ग्रोथ 2003-2004 से शुरू हो गयी थी और कह रहे हैं कि 'the economy was not prepared.' तो क्या अपोजीशन नहीं प्रिपेअर्ड था, बी.जे.पी. प्रिपेअर्ड नहीं थी, सी.पी.एम. प्रिपेअर्ड नहीं था, सी.पी.आई. प्रिपेअर्ड नहीं था, समाजवादी पार्टी प्रिपेअर्ड नहीं थी? कौन प्रिपेअर्ड नहीं था? The economy was not prepared! The Government was not prepared. और यह अर्थशास्त्र का एक सिद्धान्त है कि अगर फास्टर ग्रोथ होगी तो inflationary pressures बढ़ेंगे और उन inflationary pressures को मैनेज करना पड़ेगा, उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। यह सिर्फ Economic Survey में लिख देने से काम नहीं चलेगा। मैं मानता हूं that this is an admission of failure by the Government that they did not prepare the economy to meet the challenges of this. अब उसका नतीजा क्या हुआ? उपसभापति महोदय, उसका नतीजा यह हुआ कि अर्थ-व्यवस्था में 4 प्रकार के संकट आज के दिन हमें दिख रहे हैं। ये 4 प्रकार के संकट कौन-कौन से हैं? महोदय, मैंने आप से जिक्र किया कि high fiscal deficit. आज की अर्थ-व्यवस्था की दिक्कतों का मूल कारण है, high current account deficit. हम लोग current account deficit को positive territory में छोड़ गए थे तब इन्होंने हमारी बड़ी भर्त्सना की current account सरप्लस होता है। इसका मतलब है, इकॉनामी बेकार हो गई, ग्रो नहीं कर रही, इसलिए आपका current account surplus है। They started celebrating current account deficits. और उसी celebration का, उसी महिमा-मंडित करने का नतीजा है कि आज के दिन इस साल, the estimates, Mr. Deputy Chairman, Sir, are that current account deficit could be 3.5 per cent or 4 per cent of the GDP, which is a matter of grave concern. I have figures here which show, अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि $ 37 billion has gone out of this country since March this year. महोदय, एक जमाने में 5 बिलियन डॉलर्स, 7 बिलियन डॉलर्स का हमारा रिजर्व हुआ करता था। यह खुशी की बात है कि धीरे-धीरे करके हम उसको 300 बिलियन डॉलर्स से ऊपर ले गए। आज वह 270-274 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। $ 37 billion have left this country. Why? It is because people are withdrawing money. महोदय, इनके बारे में बता रहा था, मैं एक-दो बातें और कहूंगा, अभी हाल में fiscal deficit और इसका, उसका जो तमाशा चला, कल-परसों अखबार में यह खबर छपी जिस में सी. एंड ए. जी. ने कहा कि आप ये जो ऑइल बांड इश्यू कर रहे हैं, फर्टिलाइजर बांड इश्यू कर रहे हैं, इसमें क्या चतुराई है कि they are postponing the expenditure to a future date. कल को कोई सरकार आएगी, परसों कोई सरकार आएगी, उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि उसके मूल को, principal amount को वह पे करे। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने बजट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उपसभापति महोदय, हम लोगों ने शुरू से कहा कि, भाई, यह मत करो। ऐसा नहीं है कि आपकी जो estimated subsidy बजट के बाहर दिखना है, लेकिन इन्होंने यही काम किया। ये काबिल हैं, इसलिए इन्होंने किया, लेकिन अब सब लोगों ने इस चोरी को पकड़ लिया कि यह तो बहुत गलत है। और कंट्रोलर एंड ऑडीटर जनरल ने क्या लिखा है? उन्होंने अभी हाल में सरकार को communication भेजा है और जो बात अखबारों में छपी है, that is how I know it. सी. एंड ए.जी. ने कहा है, "We have written to the Government that issuing oil and fertilizer bonds is not fair and transparent. Issuing bonds without a provision for resources to meet the future obligation

transfers the burden to the next generation. The CAG has said, "Making our children foot the bill for us is against inter-generational equity and financial discipline." What does the C & AG say then? That this Government is indulging in financial indiscipline. This is the comment of the C&AG. अब आप देखिए कि फिसकल डेफिसिट, करंट एकाउंट डेफिसिट, प्राइज राइज़, जिसकी कोई इंतिहा नहीं है। There is a virtual standstill in the production of industrial goods. In August, it came down to 1.3 per cent, manufacturing was down to 1.1 per cent. If you take the first five months, i.e., from April to August, you will find that the growth rate stood at 4.9 per cent as against 10 per cent in the previos year. There is a trend. I am not going only by the August figures. There is a clear trend. Therefore, there is a slowing down in the Government revenue. Everyone knows that it is the industrial sector which contributes most of the revenue. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर स्लो हो गया, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू भी स्लो होंगे। Their excise duty collection, the latest figures that I have seen, are less than that of the last year's. Our direct taxes mop up. जिस पर कि बहुत फख्र हम सब लोगों को होती है कि बहुत तेजी से 40 परसेंट, 45 परसेंट बढ़ा है, that is slowing down. Industrial production decline will impact on revenue collection. So, what will happen, Sir? All this is going to impact on your growth story. So, you will have a smaller GDP base; you will have less revenue growth and you are spending like there is no tomorrow. तो क्या होगा? The fiscal deficit will balloon. तो उसके चलते our problems are going to multiply further and further. सर, इस सरकार के ऊपर मेरा चार्ज यह है कि आज कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अब बजट के ऊपर, सप्लीमेंटरी डिमांड्स के ऊपर बोल रहा हूं, तो जान की सुरक्षा के ऊपर, सिक्युरिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, but are our jobs secure? Are our investments and savings secure? No, Sir. अभी क्या हुआ कि बहुत हल्ला मचा। कुछ लोगों को हाई प्रोफाइल जोब से, हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री से निकाल दिया गया, तो बहुत शोर मचा, क्योंकि सब कुछ हाई प्रोफाइल था। इसे खुद टेलीविजन चैनल वालों ने दिखाया। फिर उनको वापस लिया गया। मेरे पास एक स्टेटमेंट है जयराम रमेश जी का, पता नहीं हाऊस में हैं या नहीं, उन्होंने कहा, जो "फाइनेन्सियल एक्सप्रेस" अखबार में 20 मार्च, 2008 को छपा था। इससे पहले वाले सेशन की बात है। "The Government on Wednesday admitted that the appreciation of rupee against dollar has resulted in a loss of about 20 lakh jobs. In certain sectors like textiles, leather, marine products and handicrafts, there is a net decilne in export which has led to job losses." यह जयराम रमेश जी ने इस सदन में स्टेटमेंट दिया था। यह अखबार की खबर नहीं है। अखबार में तो छपा on the basis of the reply that he gave in this House. About 20 lakh jobs have gone in these three sectors. Why? Because, the rupee appreciated against the dollar. It came down to around 40 rupees a dollar. तो हम लोग बहुत खुश हुए। बीस लाख जोब हाथ से निकल गए। मैं तिरुपुर के लोगों से मिला और मैं कई ऐसे लोग से मिला, जो कि केन्द्र हैं टैक्सटाइल उद्योग के, जो केन्द्र हैं लेदर उद्योग के, उन लोगों ने यही बात कही कि हम लोग एक्सपोर्ट ऑर्डर खो रहे हैं और उसके साथ-साथ जोब लोसेस भी हो रहे हैं। It is inevitable. Jobs are not secure.

उपसभापति महोदय, अब क्या हो रहा है कि वित्त मंत्री जी रोज इस बात को कह रहे हैं, प्रधान मंत्री जी ने जोर देकर इस बात को कहा है, The fundamentals of the economy are strong. 'Fundamentals of the economy are strong.' बहुत खुशी की बात है। Raise confidence, by all means. But you can't say something, which everyone knows, is untrue. If you run such high fiscal deficit, if your industrial production is collapsing, if your current account deficit is going up, if your real estate sector has collapsed, if there are job losses, will you still say the fundamentals of the economy are strong? यह हम किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जो लोग अर्थव्यवस्था को देखते हैं और थोड़ी-सी भी अक्ल रखते

हैं, उनको पता है कि fundamentals of the economy have been weakened and they have been weakened – मेरा चार्ज है उपसभापति महोदय – because of the economic mismanagement of this dream team of economic managers in the UPA Government. इसलिए fundamentals of the economy have been weakened, not because of the US crisis. The US crisis has only added to our problems, the US crisis has got reflected in the stock market, which has come down, ठीक है। मेरे पास पता नहीं कितने महीने पुरानी अखबार की कटिंग्स हैं कि लोगों ने होम लोन लिया, होम लोन लेकर वे Equated Monthly Instalments दे रहे थे, अचानक ब्याज दर बढ़ने से उनका EMI एक-तिहाई, 33 परसेंट, 40 परसेंट बढ़ गया। अब आप देखिए, लोगों के ऊपर कितनी मार पड़ी। पहले तो उनके घर का बजट गड़बड़ा गया because of the inflation दूसरा, अगर उन्होंने कोई घर बनाया था, घर खरीदा था, उन्होंने कोई कार खरीदी थी, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदा था और लोन लेकर खरीदा था तो उसमें 40 परसेंट का कम से कम इजाफा हो गया और तीसरा, अगर उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाया था, यूलिप में लगाया था, दूर-दूर से उनका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ था तो आज वह घट कर आधे से भी कम रह गया। तो हम क्या करें? हम कहें कि 'fundamentals of the economy are strong.' You have to go out to feel the pain that the people are feeling और अगर हम इस pain को नहीं देखते हैं और उसके लिए कोई उपाय नहीं करते हैं महोदय, तो मुझे लगता है कि हम और दिक्कत में पड़ेंगे। वित्त मंत्री कहते हैं कि "Its a is liquidity crisis." कुछ अर्थशास्त्रियों ने पूछा कि आपका money supply is 19 per cent, your credit growth was 24 per cent, तो where is the liquidity crisis? And, why suddenly the liquidity crisis?' Just because the FIIs have withdrawn ten billion dollars! इतनी क्षमता इस देश में नहीं है कि 10 बिलियन, 15 बिलियन डॉलर अगर कोई निकाल के ले जाए तो हमारे यहाँ crisis हो जाए और अगर यह क्षमता नहीं है तो हमने उनको यह सुविधा क्यों दी कि वह आयें? मैं पूछना चाहता हूं कि हमने Participatory Notes को क्यों पहले आने दिया? यह हो गया कि almost 50 per cent of the FII investment in this country was through participatory notes.

वित्त मंत्री जी कुछ ऐसा चेहरा बना रहे हैं जैसे कि मैं गलत बोल रहा हूं। अगर गलत बोल रहा हूं तो आप correct कर दीजिएगा, हो सकता है कि 40 परसेंट हो। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने शोर मचाया कि Participatory Notes बंद करो। You do not know whose money is it? National Security Advisor ने कहा कि टेररिस्ट्स का पैसा हमारे स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है और उसके बाद Participatory Notes के ऊपर कुछ restrictions लगाए गए। मैं इस सरकार के ऊपर यह चार्ज लगाता हूं कि इस संकट का फायदा उठाकर उन्होंने फिर Participatory Notes को छूट दे दी। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि where is the money abroad? Where is the money abroad? यह अमरीका में one trillion, यूरोप में one trillion. They are coming out with mind-boggling figures to inject liquidity into their system और वह पैसा क्या हमारे यहां आने वाला है? There is no money abroad. There is no investment which is going to come to India through the participatory notes. आप जितने दरवाजे हैं, सब को खोल दीजिए, कोई पैसा नहीं आने वाला है। तो क्यों खोला गया? इसलिए खोला गया क्योंकि Participatory Notes से आज देश का पैसा बाहर जा रहा है। अगर आपने बंद रखा होता तो यह नहीं होता। क्यों ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट खुलता है, खुल कर एक हजार प्वायंट नीचे गिरता है, उसके बाद सरकार का कोई वक्तव्य आता है, उससे ऊपर चढ़ता है फिर दूसरा वक्तव्य आता है, फिर नीचे गिरता है। स्टॉक मार्केट में यह हो क्या रहा है? उपसभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि stock market में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। I do not know whether the present Finance Minister loses his sleep over the ups and downs in the stock market. The Prime

Minister did not lose his sleep. लेकिन, इतनी नज़र रखना तो इनका कर्त्तव्य बनता है कि क्या हो रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि डाउ ज़ोन्स बहुत गिरा हुआ था, सब लोग जानते थे कि इंडिया का मार्किट खुलेगा तो धराशायी हो जाएगा। इंडिया का मार्किट खुला तो धड़ाम से एक हजार प्वाइंट नीचे आ गया। उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी आई कि हमने सीआरआर 100 या 150 बेसिस प्वाइंट खोल दिया है, फिर मार्किट थोड़ा ऊपर चढ़ा। फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिगर्स आ गए, फिर मार्किट नीचे गिरा, फिर इन्फलेशन के फिगर्स आ गए। The point I am making is, all these things can be managed unless there are vested interests which are operating in the market. And why should the Government become a party to those vested interests? Exchange market, rupee market, rupee-dollar market में क्या हो रहा है? आज मैं देख रहा था, पता नहीं कुछ 49, 50 या कितने एक रुपए का वेल्यू चला गया था। मैं वित्त मंत्री से कोई इस बात को लेकर झगड़ा नहीं कर रहा हूं कि stock market ऊपर जा रहा है या stock market नीचे जा रहा है, मैं वित्त मंत्री से इस बात को लेकर भी झगड़ा नहीं कर रहा हूं कि exchange market में रुपया क्यों ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मेरा अगर उनसे मतभेद है तो वह इस बात को लेकर है कि हाल के दिनों में जो हमने volatility देखी है, चाहे वह stock market हो या exchange market हो, That volatility is extremely unhealthy and it shows complete lack of any regulatory or Government oversight on the exchange market and the stock market. कोई मार्किट कभी भी सही ढंग से काम नही कर सकती, अगर उसमें panic रहेगा, चाहे वह ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। इसलिए, उपसभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि इन्होंने इस मुल्क में अपनी miss-management से जो क्राइसिस क्रिएट करा है और उसके बाद जो उसको diagnose ये कर रहे हैं, वह diagnose सही नहीं है और यदि diagnose सही नहीं होगा, बीमारी क्या है उसको हम नहीं पकड़ेंगे, तो हम सही दवा नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा मानना यह है कि यह सरकार आज के दिन भी जो अर्थ-संकट है, उसके लिए सही दवा नहीं दे रही है और इस अर्थ संकट पर उसी समय हम काबू पा सकते हैं, जब सरकार अपने बजट पर काबू पाए, नियंत्रण पाए।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बड़ा भारी विश्वास का संकट इस देश में पैदा हो गया है - crisis of confidence, किसी को confidence नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोगों ने एक दिन बैठकर, जो यह क्राइसिस हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा की। हम लोगों ने सोचा कि अगर हम सिर्फ सरकार की भर्त्सना करेंगे तो लोग कहेंगे कि opposition में हैं, विरोधी दल में हैं, इसलिए सरकार की शिकायत कर रहे हैं। इसलिए आपस में चर्चा करके, experts की राय लेकर, हम लोगों ने - जसवंत सिंह जी, अरुण शौरी जी और मैंने, तीनों आदमियों ने मिलकर प्रैस कांफ्रेंस की और इन तीन आदमियों में जसवंत सिंह जी और मैं, मात्र दो ही former Finance Minister थे, क्योंकि बाकी तीन जो former Finance Minister थे वे आज सरकार में हैं, तो हम दो ही लोग बाहर हैं। तो हम लोगों ने गंभीरता से विचार करके एक 12 सूत्री प्रोग्राम ऑफ एक्शन मीडिया के सामने रखा, जो हमने सोचा कि वित्त मंत्री के ध्यान में पहुंचेगा और वे 12 सूत्र क्या थे, मैं इसमें सदन का समय बर्बाद करना नहीं चाहता। लेकिन, उपसभापति महोदय, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उसमें एक बहुत अहम बात हम लोगों ने की - Please do not nibble at the margins. एक छोटा सा कदम एक दिन उठाया, दूसरे दिन फिर एक छोटा सा कदम उठाया, तीसरे दिन फिर एक छोटा सा कदम उठाया, क्या होता है उससे? उससे ऐसा लगता है कि जैसे हमें fundamental economy से concern नहीं है। We are only concerned with the stock market; we are only looking at the stock market. वित्त मंत्री महोदय, RBI यह घोषणा करती है, तो दो दिन स्टॉक मार्केट चढ़ेगा, तीसरे दिन फिर धड़ाम नीचे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने कहा उसमें 'one big bang approach' अगर आप में इच्छा शक्ति है ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, jammer is not working; mobile phones are ringing. It is a security hazard. Here jammer is put on only for security reason, not for any other reason. It is not a noise pollution, but only for security reason there is a jammer. It is a very sophisticated jammer but I don't know why and how bells are ringing.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal) : I am happy to note that it is not only my phone. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: I don't bring my phone in the House. But I would like to make a point. ...*(Interruptions)*... Yechuriji was speaking in the chamber on phone. How is it possible? Is he using a different type of gadget, which is breaking the norms of the jammer? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a serious matter. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: How is it possible? It should be investigated. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: I am happy that it is not only my phone and, in fact, more phones are ringing on the other side. It is a security threat. ...*(Interruptions)*...

श्री यशवंत सिन्हा: उपसभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि सिर्फ liquidity का संकट नहीं है।

श्री उपसभापति: सिन्हा जी, अभी आप कितना समय और लेंगे?

श्री यशवंत सिन्हा: मैं बस 4-5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि सिर्फ liquidity का संकट नहीं है, गलत diagnosis, गलत medicine. मैं सरकार के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को इतना याद दिलाना चाहूंगा कि 1991 में भी एक अर्थ-संकट इस देश में आया था। उस समय मैंने पद छोड़ा था और डा. मनमोहन सिंह जी, वित्त मंत्री बने थे। उस समय श्री नरसिंह राव जी, इस देश के प्रधान मंत्री थे। सरकार बनने के बाद श्री नरसिंह राव जी ने पहला काम यह किया कि उन्होंने सारे दलों को बुलाया कि अर्थव्यवस्था में बहुत गंभीर संकट है, इससे कैसे निपटा जाए। चूंकि मैं outgoing Finance Minister था, इसलिए मुझे बोलने के लिए पूरा समय दिया गया कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या करते और उस समय मैंने जो सुझाव दिए थे, उनमें से बहुत सारे सुझावों का अनुसरण हुआ। आज इस देश की पोलिटिक्स को क्या हो गया है? इतना बड़ा संकट अर्थव्यवस्था में आया हुआ है, यदि हम लोगों को कोई अक्ल नहीं है, तो और किसी को बुला लो, बहुत सारे लोग हैं, जो आपको मशविरा दे सकते हैं, हमारे वामपंथी मित्रों ने बहुत दिनों तक आपको न्यूक्लियर डील के ऊपर मशविरा दिया है, हो सकता है कि वे इस पर भी आपको मशविरा देने के लिए तैयार हो जाएं, where is that culture कि सबको लेकर चलो, सबसे बातचीत करो, सबके सुझावों को लो। हमने 12 सुझाव दिए हैं, वित्त मंत्री जी का एक बयान तक नहीं आया कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अच्छा काम किया है, इसलिए हम उनसे बात करेंगे। वे बात नहीं करेंगे, हमें भी कोई बहुत प्रसन्नता नहीं होगी उस कमरे में जाकर, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि This reflects the style of functioning of this Government that you don't take the Opposition, that you don't take the parties into confidence. ...*(Interruptions)*... You are running away from Parliament. You know better than me what is happening to that. तो कैसे होगा? How do we build national consensus on issues? There cannot be a national consensus. मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के सामने जो संकट है, हमारा बनाया हुआ संकट है और उसके बाद जो विश्वव्यापी संकट है, उसकी अभी हमारे देश में शुरुआत हुई है, अभी job losses शुरु हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि लाखों लोग बेरोजगार होने वाले हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज जिन बैंकों में liquidity है, वे भी कंपनियों को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज small and medium enterprises को working capital loans नहीं मिल रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानता हूं, दूसरे क्षेत्रों के बारे में जानता हूं जहां बैंकों को हिदायत दी गई है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर पैसा मत दो और नतीजा यह होता है कि बैंक वाले किसानों को घुमाते है, टहलाते हैं, मत दो पैसा, नया क्रेडिट कार्ड मत issue करो, पुराने क्रेडिट कार्ड में कोई न कोई उलझन लगा कर पैसा मत दो। Liquidity is not the

problem. Confidence is the problem. आज के दिन उन लोगों का विश्वास न तो इस व्यवस्था में है और न ही इस सरकार में है और कब होगा, होगा कि नहीं, यह मैं नहीं जानता हूं। The only silver lining, Mr Deputy Chairman, that I see in this approaching gloom, the only silver lining is कि यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है, उसके बाद यह अपने घर जाएगी और लाखों-करोड़ों का बोझा आने वाली सरकार के ऊपर छोड़ कर जाएगी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो धूल में मिल गई होगी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी हर किनारा फटेहाल होगी, यह सरकार इस तरह की अर्थव्यवस्था को छोड़ कर जाएगी। मैं आज से चार-साढ़े चार साल पहले जो बात कही थी, इसी सदन में मैंने कही थी कि we have seen Chidambaram Mark-I. Chidambaram Mark-I took two years to bring the economy to a halt. Let us see how long Chidambaram Mark-II takes. And, I am sorry to say he has proved his mettle, or whatever it is, within four years. Thank you, Sir.

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Thank you very much Mr. Deputy Chairman, Sir. I am here to support the Finance Minister of this country who has approached this House for supplementary demands. My previous speaker who was also one-time Finance Minister and the Budget is presented by the present Finance Minister. The previous speaker started with the size of the booklet. In fact, size should not be the criterion; the content should be the criterion because if we refer to size and colour, many years ago, it was white which was treated as beauty and now black is treated as beauty all over the world. And, robust size is not approved by Ayurveda. One may be thin, one may be fat. What is written in the book is more important. No doubt, I have one advantage to speak here because he was ex-Finance Minister and Mr. Chidambaram is the present Finance Minister. He was also an ex-Finance Minister. He was also ex-Finance Secretary. But, I have worked at very bottom of the Finance Department for 37 years. I was a Clerk in Customs and Central Excise Department. I was a Sub Inspector in the same Department. I was Inspector in the Central Excise Department, I was an Inspector in the Income Tax Department. I was Income Tax Officer for 17 years in the Income Tax Department and I was Assistant Commissioner for Income Tax for eight years. So, I have experience of both the Departments and the Finance Ministry. I have also experience of work under both these gentlemen. When I was working in the Department, Mr. Yashwant Sinha was the Finance Minister. When I was working in the Department, hon. Mr. P. Chidambaram was also the Finance Minister. But I never used to meet them because I was a very small man. Today, I am in Rajya Sabha and I will utilise this opportunity to talk about the issue. It will not be the fiscal deficit; it will not be the GDP; it will not be problem faced by this country of the other countries; it may also not be stock exchange because, at least, personally I am not concerned about stock exchange. I will talk about the issues of the poor people; I will talk about the issues of the working class; I will talk about the issues of the Government employees. And, all said and done, how many below poverty line families are taken to above poverty line. That should be the main criterion of any governance. Sir, I am happy and I must congratulate the UPA Government because this is the first Government in this country which has given annual report card every year in the month of May. The report card, giving complete data about what is done by the Government during one year, is presented by the Indian Prime Minister and supported by the hon. Finance Minister. And the last report card was presented

to the people of the country in the month of May 2008. This is the first UPA Government which had not only presented the Budget, but also presented the Performance Budget to the people of this country. This is the first UPA Government which has given details regarding Gender Budgeting, which was not done by the previous Government. This is the first Government which has introduced very novel scheme like the National Rural Employment Guarantee Act.

The hon. Member, who spoke before me, definitely referred to the Debt Relief Fund, the Sixth Central Pay Commission, and the National Rural Employment Guarantee Act. He is right. I also agree with him that no provision was made in the Budget for debt relief, or no provision was made in the Budget for the Sixth Central Pay Commission. But he should appreciate that it is the first Indian Government which had accepted the Report of the Pay Commission on its presentation by the Commission and arrears to the tune of forty per cent are already paid to the Central Government employees all over the country before Diwali this year, and the balance will be paid in the next year. That was not done by the previous Government. It should go on record. I would like the hon. Finance Minister to look into various issues which require urgent attention as far as employees are concerned first, and then about other various schemes and grants also.

Looking at the collection, bumper collection was made by the employees working in the Income Tax Department, the Customs Department, and the Central Excise Department. And as a matter of appreciation, the Union Finance Minister last year gave one per cent incentive grant to the employees and officers of the-Department and according to my information – it may be right and it may be wrong also, but if I am wrong it may be verified – Rs.196 crore was given to the Income Tax Department and the Customs Department as incentive money to be utilised for infrastructure. But I am told by the Employees' Federation yesterday only that Rs.196 crore was mainly utilised by Group 'A' officers of the Department and a very small percentage of money went to the employees belonging to the Class III and Class IV. For example, they only gave mobile phone to the class III and Class IV employees. But that was not done on the basis of work or its importance. Suppose an inspector goes for surveying the market or a clerk goes to the rural area for a Government work, he should be provided with the mobile phone. But what happened was, the power to distribute mobile phone was given to a senior officer. So, naturally, the senior officer gave mobile phone to his driver, his peon, and his cook. And the inspector, who is actually doing the work of the Government, is not provided with the mobile phone. Mobile phone was distributed on the basis of percentage of a particular range. That is wrong. I request the hon. Finance Minister to look into the matter and see that justice is done to the employees of Group 'B', Group 'C', and Group 'D'.

As far as the Sixth Central Pay Commission Report is concerned, a very serious complaint is there among the Government employees, in particular belonging to all Central Government Departments. It is true that the recommendations are accepted, but the fitment formula regarding increase in the pay has given advantage only to Group 'A' Officers where the increase is to the tune

of 180 per cent and whereas employees working at the lower level are getting only 40 per cent benefit. Something has to be done by the Government. If necessary, it should be revised. For giving benefit, parity should be there. If it is being given on the basis of a percentage, then it should be 100 per cent for all or 40 per cent for all. A Group 'A' officer gets 150 per cent benefit on account of the Pay Commission whereas Group 'C' and Group 'D' people get only 40 per cent? It amounts to discrimination and it requires to be looked into.

Now I come to a very serious issue which is merger of banks. My personal experience as Member of the Lok Sabha earlier and as Member of the Rajya Sabha now is that banks have become state within state. We approached the Central Government and various State Government Departments in the capacity of people's representatives. There may be an issue of loan. There may be an issue of recovery.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rashtrapal, please. A statement has to be made by the Minister.

STATEMENT BY MINISTER

Recent Developments in Sri Lanka

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I rise to apprise this august House of the recent developments in Sri Lanka.

The situation in Sri Lanka is of serious concern to the Government, in particular the deteriorating humanitarian situation in the Northern part of Sri Lanka. We are concerned about the plight of the civilians caught in the hostilities and the growing number of internally displaced persons. We have emphasised to the Sri Lankan Government that the safety and the security of the civilians must be safeguarded at all costs and that food and essential supplies be allowed to reach them unhindered. We have been assured that the safety and well being of the Tamil community in Sri Lanka will be taken care of. In this connection, Member of Parliament and Senior Adviser to the President of Sri Lanka, hon. Basil Rajapaksa is due to visit India shortly.

Let me reiterate our conviction that there in no military solution to the ethnic conflict. What is required in Sri Lanka is a peacefully negotiated political settlement within the framework of a united Sri Lanka respecting the legitimate rights of the minorities including the Tamil community. The rights and the welfare of the Tamil community of Sri Lanka should not get enmeshed in the ongoing hostilities against the LTTE. We encourage the Government of Sri Lanka to continue to nurture the democratic process in the Eastern Province as well.

The Government has also taken up with the Sri Lankan Government the need to ensure the safety of our fishermen. While it is important for our fishermen to respect the International Maritime Boundary Line, we have impressed on the Sri Lankan Navy to desist from firing on Indian fishermen. Our two Governments have agreed to work towards concluding practical arrangements to prevent such incidents.

Re: Clarifications with regard to statement by Minister about Development in Sri Lanka

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Clarifications will be later. ...*(Interruptions)*...